ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

31 जनवरी, 2018 • वर्ष 1, अंक 2

सात दिन – सात पृष्ठ

- मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना
- शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी
- पूर्वांचल बैंक की 25 शाखाओं का शुभारम्भ
- तकनीकी क्षेत्र में शोध को बढ़ावा

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

विकास कार्यों को प्राथमिकता

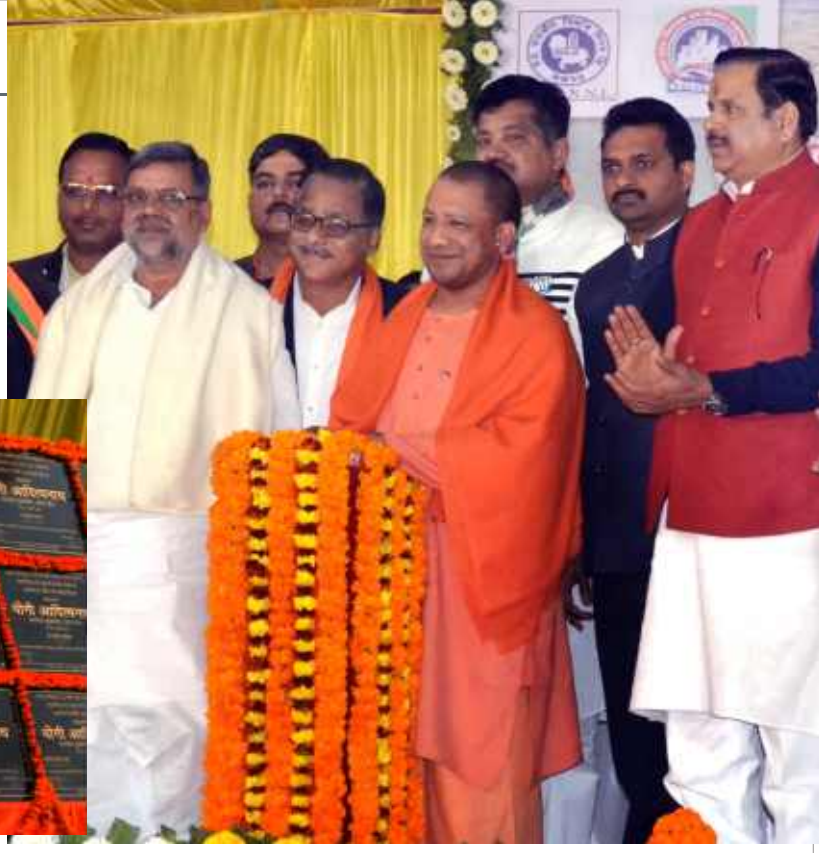

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर भ्रमण के दौरान के भटहट में 9781.52 लाख रुपये की लागत की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई 05 परियोजनाओं की लागत 8113.17 लाख रुपये तथा लोकार्पित 10 परियोजनाओं की लागत 1668.35 लाख रुपये है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। इससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री जी ने आई.टी.आई. संस्थान का शिलान्यास भी किया। इस संस्थान के बन जाने से स्थानीय नौजवान बिना कहीं बाहर गये, यहीं पर दक्ष हो सकेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेन्ट योजना के तहत भी प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं में कौशल विकास से उनके लिए रोजगार की तलाश आसान हो जाती है। प्रशिक्षित युवा नौकरी के साथ–साथ स्वरोजगार हेतु भी सक्षम होते हैं। रोजगार के माध्यम से क्षेत्र का विकास सम्भव है। यह हर तबके के चहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम है।

राज्य सरकार द्वारा गरीबों, वंचितों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं आदि को ध्यान में रखकर योजनाएं बनायी जा रही हैं।

1.40 लाख युवाओं को कौशल विकास में पारंगत कर नौकरियां दी जा रही हैं। जल्द ही 1.62 लाख पुलिस की भर्तियां भी की जाएंगी। युवा भर्ती की तैयारी करें, पूरी ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया होगी।

सरकार की योजनाओं से लाखों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। फसल ऋण मोचन योजना से 86 लाख किसानों को लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। राज्य सरकार हर गरीब के घर बिजली पहुंचाने का कार्य कर रही है।

राज्य सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य करा रही है। मण्डी समितियों को पुनरुद्धर किया गया है, जिससे किसानों को सुविधा और लाभ मिल रहा है। एक समय पूर्वान्चल चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन धीरे–धीरे यहां की चीनी मिलें बन्द होती चली गयीं, जिन्हें पुनः आरम्भ कराया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाकर रोजगार सृजन किया जा रहा है। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। 1.37 लाख सहायक अध्यापकों की भी भर्ती की जाएंगी। साथ ही, 20 हजार माध्यमिक शिक्षक भी भर्ती होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 60 हजार भर्तियां की जाएंगी।

गांव में महिलाओं के स्वयं सेवी सहायता समूह बनाये जाएं और उन्हें अनुदान एवं ऋण दिलाया जाए, जिससे वह अपना कुटीर उद्योग लगा सकें।

हाईस्कूल तथा इंटर की नकलविहीन परीक्षाएं सुनिश्चित कराई जाएं : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 06 फरवरी, 2018 से आरम्भ हो रही माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में हर स्तर पर नकलविहीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह विचार शास्त्री भवन में प्रदेश के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। योगी जी ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बैकअप के लिए जेनरेटर की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि छात्र–छात्राओं की चेकिंग परीक्षा से पहले केन्द्र के बाहर की जाए। छात्राओं की चेकिंग सिर्फ महिला कक्ष निरीक्षकों/अध्यापिकाओं द्वारा ही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर नकल की सामग्री, मोबाइल इत्यादि न पहुंचे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कॉलेज मैनेजमेण्ट के लोग परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि से दूर रहें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने की सामूहिक जिम्मेदारी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों की होगी। नकल की शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समस्त जिलाधिकारियों को माह अप्रैल, 2018 में जल जनित तथा विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियों जैसे–डेंगू, जे.ई., कालाज़ार इत्यादि के विरुद्ध एक पखवाड़े तक अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी तथा पीएचसी में डॉक्टरों तथ पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए। इसके अलावा, बच्चों को होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए पीडियाट्रिक्स के विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे पी.एच.सी. सी.एच.सी. का औचक निरीक्षण

इस सम्बन्ध में एक जन–जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। साथ ही, बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी इसी अभियान के साथ संचालित किया जाए। इसमें जनप्रतिनिधियों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में एक बैठक आगामी मार्च, 2018 में आयोजित की जाएगी, जिसमें इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि '108' और '102' एम्बुलेन्स सेवाओं की शिकायतों को शीघ्र दूर किया जाए। सभी जिलाधिकारी, जिला अस्पतालों, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. का स्वयं निरीक्षक करके वहां की व्यवस्थाएं चुस्त–दुरुस्त करना सुनिश्चित करें।

योगी जी ने कहा कि जिला अस्पतालों, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. की की व्यवस्थाओं की चेकिंग करने के लिए मुख्यालय से भी टीम जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अप्रैल, 2018 से जिला अस्पतालों, सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. का औचक निरीक्षक करेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को जनता की समस्याओं का जनपद स्तर पर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यद्यपि जनपद स्तर पर इसमें सुधार आया है, परन्तु निचले स्तरों विशेषकर तहसील स्तर पर समस्या ज्यों की त्यों है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गरीबों, किसानों की छोटी–छोटी समस्याएं होती हैं, जिनका समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह समस्याएं शासन तक पहुंचीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रातः 10 से 12 बजे के बीच जनता की समस्याओं को सुनने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

गोरखपुर में पूर्वांचल बैंक की 25 शाखाओं का शुभारम्भ

बैंक दें छोटे उद्यमियों को ऋण

ऋण मिलने से छोटे उद्यमियों के लिये उद्योग स्थापित करना होगा आसान

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बैंक शाखाएं खोली जाएं, जिससे लोगों को सुविधा मिले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को जनपद गोरखपुर के भ्रमण के दौरान पूर्वांचल बैंक की 25 नई बैंक शाखाओं का शुभारम्भ किया। योगी जी द्वारा जनपद देवरिया की एंठी अकटही बाजार, रतसिया कोठी, महुआडीह, कोटवा, जनपद महराजगंज की सिसवा मुंशी, सेखुआनी, सिंघपुर तलही, बभनौली चौक, बारात गाड़ा, जनपद कुशीनगर की खैरठवा, पकवा इनार, पकड़ी बाजार, भैरौगंज, नौरंगिया चौराहा, पडरही, जनपद सिद्धार्थनगर की पेरारी बुजुर्ग, कर्मा बाजार, पिपरहवा, मसीना खास, टड़वा, ठोठरी बाजार, पंचमोहनी, जनपद बस्ती की श्रृंगीनारी, चौरी तथा जनपद इटावा की बिरारी स्थित केन्द्रीयकृत बैंक शाखाओं का शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करते हुए 25 नई शाखाओं का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक छोटे उद्यमियों को ऋण दें, जिससे उनको उद्योग स्थापित करने में सहायता मिले। उन्होंने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बैंक शाखाएं खोली जाएं, जिससे लोगों को सुविधा मिले।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना में लोगों को बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोग अपना रोजगार आरम्भ कर देश व प्रदेश के विकास में सहयोग करें। इससे देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और बैंक भी मजबूत होंगे।

महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता

'समुत्कर्षा' शिविर का उद्घाटन

योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बन के लिए लिए किया जा रहा है अग्रसर

गांवों में स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इलाहाबाद भ्रमण के दौरान विद्या भारती क्षेत्रीय बालिका शिविर के 'समुत्कर्षा' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव से मातृत्व प्रधान संस्कृति रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नेतृत्व देश को प्रदान कर रही हैं। देश की विदेश मंत्री, लोकसभा की स्पीकर, देश की रक्षा मंत्री के रूप मे कार्य कर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को विश्व के सामने रखा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। 'बेटी–बचाओ बेटी–पढ़ाओ' अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। स्टैण्ड–अप योजना का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को और आगे बढ़ाना है।

हर गांव में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके स्वावलम्बन एवं सम्मान के लिए महिलाओं से सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था का गठन

बहन–बेटियां की सुरक्षा के उद्देश्य से एण्टी रोमियो स्क्वॉयड चलाया गया। 24 घण्टे संचालित निःशुल्क '181' हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाएं स्वयं को सुरक्षित कर सकती हैं। '1090' की हेल्पलाइन भी महिला के लिए प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

हर गांव में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके स्वावलम्बन एवं सम्मान के लिए महिलाओं से सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में 60 हजार ग्राम पंचायतें हैं तथा हर ग्राम पंचायत में एक स्वयंसेवी समूह गठित कर दिया गया है। महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं शिविरों के आयोजन से महिलाओं को इन योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी द्वारा 1000 क्षमता के बहुउद्देशीय भवन, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, सभागार, उद्भवन केन्द्र, दिव्यांगजनों हेतु विभिन्न निर्माण कार्य, शुद्ध पेयजल आपूर्ति संयंत्र एवं पश्चिमी अबाधित विद्युत आपूर्ति उपकेन्द्र, व्यायामशाला, 320 सीटेड छात्रावास, डाइनिंग हॉल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाई–फाई सुविधा एवं वाहन पार्किंग का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। परिसर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 2000 लीटर प्रति घण्टा वाले 2 संयंत्रो की स्थापना की गयी। इन आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और वे अपने तकनीकी कौशल से देश को लाभान्वित कर सकेंगे।

तकनीकी क्षेत्र में

शोध को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर में 7876.17 लाख रु0 के विभिन्न कार्यो का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एच.बी.टी.यू.) प्रदेश का एक गौरवशाली संस्थान है, जिसने इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह विश्वविद्यालय प्राविधिक क्षेत्र की ख्याति प्राप्त संस्थाओं में अग्रणी स्थान रखता है।

इस अवसर पर आई.आई.टी. कानपुर और एच.बी.टी.यू. के बीच इनोवेशन और इंक्यूबेशन के सम्बन्ध में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। इसके अलावा, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश,

प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान सरकार कदम उठा रही है।

लखनऊ तथा आई.आई.टी., कानपुर के बीच एक अन्य एम.ओ.यू. भी हस्ताक्षरित हुआ। इस एम.ओ.यू. के तहत आई.आई.टी. कानपुर, ए.के.टी.यू. के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। ए.के.टी.यू. पाठ्यक्रमों और अनुभवी शिक्षकों को चिन्हित कर आई.आई.टी. कानपुर को जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने में मदद करेगा।

आई.आई.टी, ए.के.टी.यू. सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के लिए वर्कशॉप, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और लघु पाठ्यक्रमों को ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। शिक्षकों के लिए ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आई.आई.टी. कानपुर तथा एक्सटेंशन सेण्टर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। आई.आई.टी. और ए.के.टी.यू. तकनीकी क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देंगे।

इन एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप नवाचार, कौशल विकास एवं शोध के क्षेत्र में प्रगति होगी तथा नौजवानों के सपने साकार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए वर्तमान सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हर खेत का मृदा परीक्षण हो, ताकि किसान अपनी जमीन के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जान सकें। उन्होंने किसानों को तकनीकी लाभ पहुंचाने के लिए स्कूलों की लैब का प्रयोग किए जाने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए

महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री अवास योजना के अन्तर्गत बनेंगे 25 हजार मकान

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और गरीबी के कारण बेघर परिवारों और जीर्ण–शीर्ण घरों में रह रहे गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान दिए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में 25 हजार चयनित परिवारों को आवास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित योजना में 25 वर्ग मीटर के आवास बनाए जाएंगे। इसमें रसोई घर भी बनाना होगा। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक आवास पर 1.20 लाख रूपये तीन किश्तों में दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में 1.30 लाख रूपये दिए जाएंगे। लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी दी जाएगी। वहीं, नक्सल प्रभावित जिलों में 95 दिन की मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। इस आवासों में शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराया जाएगा। लाभार्थियों को स्वयं 12 महीने में आवास का निर्माण करना होगा। योजना में चयनित परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार दिया गया है।

ये होंगे पात्र

बाढ़ से बेघर हुए परिवार, कालाजार से प्रभावित परिवार, वनटांगिया और मुसहर वर्ग के परिवार, जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित परिवारों को योजना के दायरे में रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल न हुए ऐसे करीब 25 हजार परिवारों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

सैनिक और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को नौकरी

योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। यह लाथ थल, जल व नभ सेवा व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2017 से लागू मानी जाएगी।

यह फैसला शहीदों के बलिदान के प्रति राज्य सरकार की कृतज्ञता होगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में लिए जाने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है। यह सुविधा पूर्व से मिल रही सुविधा या सहायता के अतिरिक्त होगी। इस संबंध में विभागवार रोस्टर बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव शामिल होंगे। सशस्त्र सैनिक बलों के लिए सैनिक कल्याण विभाग व अर्धसैनिक बलों के लिए गृह विभाग नोडल विभाग होगा।

ऐसे करना होगा आवेदन

तीनों सेनाओं से जुड़े शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन पत्र सैनिक कल्याण विभाग व अर्धसैनिक बल के लिए प्रदेश के गृह विभाग को देना होगा। इस पर शहीद सैनिक व उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। सैनिक कल्याण व गृह विभाग शहीद आश्रितों के आवेदन पत्रों को विभागों के रोस्टर प्रणाली के तहत नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजेगा। परिवार में नौकरी के लिए एक से अधिक पात्र आश्रित होने पर वरीयता में पहले आने वाले आश्रित को अवसर मिलेगा। यदि वह अपनी वरीयता हस्तांतरित करने का लिखित घोषणापत्र देता है तो अगली वरीयता के आश्रित को नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। रिटायरमेंट की आयु पूर्ण करने के पश्चात् नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

पात्रता का क्रम

शहीद के विवाहित होने पर क्रम से पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो), पुत्र/विधवा पुत्रवधू/अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्र/पुत्रियां, पिता/माता। इनकी शारीरिक व मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र व अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे। यदि शहीद अविवाहित है तो पिता, माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, विवाहित भाई क्रम से आएंगे।

नगर निकायों की नियुक्तियों के अधिकार बहाल

कैबिनेट ने नगर निकायों की नियुक्तियों के अधिकार को बहाल कर दिया है। इससे नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्षों के नियुक्ति के अधिकार पूर्ववत बने रहेंगे।

वेंडर के जरिए ही स्पीड गवर्नर लगाने की बाध्यता खत्म

कैबिनेट ने वाहनों में स्पीड नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों में किसी संस्था के जरिए 'स्पीड गवर्नर' लगाने की बाध्यता की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति मनचाहे स्थान से अपने वाहन में यह उपकरण लगवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमीट्रिक के बाद मिलेगा सस्ता राशन

अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित दर की दुकानों से गरीबों को मिलने वाला खद्यान्न बिना बायोमीट्रिक के नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने जून 2018 तक सभी उचित दर की दुकानों में ई पॉज मशीन लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे वितरण व्यवस्था की ऑनलाइन मानीटरिंग भी की जा सकेगी। पहले दो चरण में शहरी क्षेत्रों की 13144 उचित दर की दुकानों को इन मशीनों से लैस किया गया था। अब ग्रामीण क्षेत्रों की 67628 दुकानों में भी ये मशीनें लगाई जाएंगी।

अब पल्प पेपर पर छपेंगी किताबें

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलने वाली पाठ्यपुस्तकें पल्प पेपर पर छपेंगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की मुद्रण व प्रकाशन नीति 2018–19 को मंजूरी दे दी। पाठ्यपुस्तकों की प्रकाशन व मुद्रण नीति में शेष नियम व शर्तें 2016–17 व 2017–18 की नीति के समान ही रहेंगी। आगामी शैक्षिक सत्र में पल्प पेपर पर छपी किताबें वितरित की जाएंगी। पहले फरवरी में नीति को मंजूरी दी जाती थी, इस बार सरकार ने जनवरी में नीति को मंजूरी दी है।

बलिया के रसड़ा में विद्युत उपकेंद्र बनाने को मंजूरी

सरकार ने बलिया जिले के रसड़ा में 400 केवी क्षमती के ट्रांसमिशन उपकेंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सरकार के प्रयास को गति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 424.06 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन को यह काम सौंपा गया है। 30 महीने में उपकेद्र का काम पूरा करना होगा।

ओएफसी बिछाने व टावर लगाने के लिए जमा करना होगा प्रशासनिक शुल्क

नगर निकाय सीमा क्षेत्र में भूमिगत 'अप्टिकल फाइबर केबल' (ओएफसी) बिछाने के लिए सड़क की खुदाई करने से पहले ही संबंधित संस्था को आवेदन के साथ प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। सरकार ने प्रति किमी.1000 रूपये की दर से प्रशासनिक शुल्क तय किया है। इसी तरह मोबाइल टावर लगाने के लिए भी प्रति टावर 10,000 रूपये की दर से प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद ही ओएफसी बिछाने व टावर लगाने की अनुमति दी जाएगी।

'उत्तर प्रदेश दिवस' के माध्यम से युवाओं को अपने विचार रखने का मंच मिला

वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश अब प्रगति की राह पर है और उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। अब यह सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शीघ्र ही देश का अग्रणी और विकसित राज्य होगा। उत्तर प्रदेश को विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिल–जुलकर काम करना होगा।

राज्यपाल जी ने यह विचार अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 'उत्तर प्रदेश दिवस' के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के गठन के 68 वर्ष बाद यहां पर पहला 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाया जा रहा है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाने का सुझाव उन्होंने सरकार को दिया था, जिसे

मानते हुए इसका आयोजन किया गया है। तीन दिन के इस आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न रंग देखने को मिले, जिससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति कितनी समृद्ध है।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 24 जनवरी, 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, परन्तु इसका स्थापना दिवस आज तक कभी नहीं मनाया गया। वर्तमान सरकार द्वारा पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को अपने विचार रखने का मंच मिला है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की परम्परा, विरासत, कला, उद्यम के अलावा किसानों, युवाओं और शिल्पियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, जिसके माध्यम से वे आने वाले वर्षों में इसका उपयोग प्रतिभा प्रदर्शन के लिए कर सकेंगे।

'उत्तर प्रदेश दिवस' में प्रतिभाग करने के उत्साह के चलते तीनों दिन बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह 'एक जनपद एक उत्पाद' के प्रति देखा गया। राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में इस योजना के माध्यम से 20 लाख रोजगार मुहैया कराएगी।

सूचना विभाग की वेबसाइट और 'ई–सन्देश' को गवर्नर और सीएम ने लॉच किया

उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। इसके पास देश को नेतृत्व देने की क्षमता है। स्टार्ट–अप योजना के माध्यम से युवाओं के 'इनोवेटिव आइडिया' को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार अगला वित्तीय वर्ष युवाओं को समर्पित करने जा रही है। अगले वर्ष युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा।

योगी जी ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर प्रदेश की साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों की महान विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है, वे अपने–अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि युवा उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी शीर्ष पर पहुंचने के लिए काम करेंगे।

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। 06 लाख युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकृत करते हुए, उनका कौशल विकास किया गया। इनमें से 01 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना चाहती है, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी